



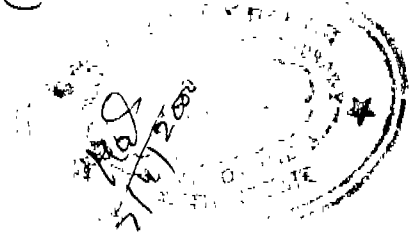
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 1999/अग्रहायण 22, 1921
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 1999/AGRAHAYANA 22, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1999

सा.का.नि. 811 (अ).—जबकि आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध अभिसमय दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत एक दूसरे को अधिसूचित करने पर सितम्बर, 1999 के 27वें दिन को प्रवृत्त हो गया है।

अतः अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और धन कर अधिनियम, 1967 (1967 का 27) की धारा 44क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के समस्त प्रावधान भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबन्ध

आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार

और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

चेक गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और चेक गणराज्य की सरकार, आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन की दृष्टि से एक अभिसमय निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:—

अनुच्छेद-1**वैयक्तिक क्षेत्र**

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2**अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर**

1. यह अभिसमय उन करों पर लागू होगा जो एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए जाते हैं। चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं।
2. सकल आय, सकल पूंजी पर आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय तथा पूंजी पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगने वाले करों, उद्यमों द्वारा अदा किए गए खेतनों तथा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले करों की राशि भी शामिल है।
3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

(i) आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार ; और

(ii) धनकर ;

(जिसे इसके बाद “भारतीय कर” कहा जाएगा);

(ख) चेक गणराज्य में :

(i) व्यष्टियों की आय पर कर ;

(ii) विधिक व्यक्तियों की आय पर कर ;

(iii) अचल सम्पत्ति पर कर ;

(जिसे इसके बाद “चेक कर” कहा जाएगा);

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समरूप करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद पैराग्राफ 3 में उल्लिखित विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद-3**सामान्य परिभाषाएं**

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) “भारत” पद से अभिप्रेत है—भारत का राज्य-क्षेत्र तथा इसमें उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा इसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और अन्य कोई भी समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;
- (ख) “चेक गणराज्य” पद से अभिप्रेत है—चेक गणराज्य का राज्य-क्षेत्र जिसके ऊपर यह चेक कानून के अंतर्गत और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार चेक गणराज्य के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता हो;
- (ग) “व्यक्ति” पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है।
- (घ) “कम्पनी” पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;
- (ङ.) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;
- (च) “अन्तरराष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है—दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा परिचालित कोई जलयान अथवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

- (i) भारत में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (ii) चेक गणराज्य में, वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

- (i) दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
- (ii) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(झ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

- (i) भारत के मामले में, "पूर्ववर्ती वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है;
- (ii) चेक गणराज्य के मामले में, पहली जनवरी को शुरू होने वाली बारह मास की अवधि;

(ञ) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षानुसार भारतीय कर अथवा चेक कर अथवा चेक कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उक्त करों के सम्बन्ध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो जिस पर यह अभिसमय लागू होता हो अथवा जो उन करों के सम्बन्ध में लगाए गए अर्धदंड की द्योतक हो;

.(ट) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य अथवा चेक गणराज्य अभिप्रेत है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी पद का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड से वहां पर कर लगाया जा सकता है। परन्तु इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से अथवा उसमें स्थित पूंजी से प्राप्त आय के बारे में ही कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नलिखित के अनुसार तय की जाएगी :

- (क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) घनिष्ठतर हैं;
- (ख) यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- (ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;
- (घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अनुच्छेद-5 स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।
2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :
 - (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
 - (ख) कोई शाखा;
 - (ग) कोई कार्यालय;
 - (घ) कोई कारखाना;
 - (ङ) कोई कार्यशाला;
 - (च) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
 - (छ) कोई बिक्री बाजार;
 - (ज) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो; और
 - (झ) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, चानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों।
3. कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य, संयोजन अथवा प्रतिष्ठापन परियोजना अथवा उससे सम्बन्धित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप छह महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों।
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :
 - (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;
 - (ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;
 - (घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।
 - (ङ) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।
 - (च) केवल उप-पैराग्राफ (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक प्रकार का हो।
5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां पर स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट के अलावा कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का ऐसे कार्यकलापों के संबंध में, जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:
 - (क) उस राज्य में उक्त उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह उस प्राधिकार का आदतन प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक ही सीमित न हों, जिनका यदि किसी निश्चित कारोबारी स्थान से प्रयोग किया जाए तो उस बात से ही उस पैराग्राफ के उपबन्धों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
 - (ख) उसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किंतु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो।
6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का, पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा यदि यह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों के लिए बीमा करता है।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों तथापि जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें विचारार्थीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के अधिसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भंडार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं तथा वायुयान और मोटर वाहन अचल सम्पत्ति नहीं समझे जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा उनके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए हों।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों तथा वे उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा उस राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के अधधीन किए गए हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की खरीद की गई है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां आय की मदों में लाभों की वे मदें शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

जहाजरानी और वायुपरिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रयुक्त आधानों (आधानों के परिवहन के लिए ट्रेलरों और अन्य उपकरणों सहित) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा उन्हें किराये पर देने से किसी संविदाकारी राज्य के निवासी किसी परिवहन उद्यम द्वारा प्राप्त किए गए लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि उक्त आधानों का केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही प्रयोग किया जाता हो।
3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से सीधे संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।
4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-9

संबन्ध उद्यम

जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और तदनुसार उन पर कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी, एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो लाभों में भागीदारी के ऋण दावे नहीं हों तथा अन्य ऐसे अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिस राज्य की वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा

किया जाता हो अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद-11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा जिसमें वह उद्भूत होता है, किंतु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज को उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यशर्त कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और उनके हितभागी स्वामित्व में हो अथवा उनके द्वारा दिए गए किसी ऋण अथवा बढ़ाए गए क्रेडिट के संबंध में प्राप्त किया गया हो अथवा उनके द्वारा समर्थित किया गया हो :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत का निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत का लघु उद्योग विकास बैंक और भारत का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई सी आई सी आई); और

(ii) चेक गणराज्य के मामले में, चेक नेशनल बैंक (सी एन बी), चेक एक्सपोर्ट बैंक (सी ई बी), निर्यात गारंटी और बीमा कंपनी (ई जी ए पी) और कॉसोलिडेशन बैंक (के ओ बी); अथवा

(ग) कोई अन्य संस्था जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हो सके।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावे चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं। विलम्ब अदायगी के लिए जुर्माने को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज देने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसा विशेष संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा किंतु यदि रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियों" पद से अभिप्रेत है—चल चित्रदर्शी फिल्मों और रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण हेतु फिल्मों अथवा टेप सहित किसी साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति का स्वामित्व, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां;

(ख) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है— प्रबंधनीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगियां जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कार्पिकों द्वारा सेवाओं का प्रावधान भी सम्मिलित है किन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए अदायगियां सम्मिलित नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो लागू होंगे।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई नियत स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उसके प्रयोगाधिकार अथवा जानकारी जिसके लिए उसकी अदायगी की गई हो, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा।

अनुच्छेद-13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

3. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन एवं इससे संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न, किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाषों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद-14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में कराधेय होगी :

- (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा
- (ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां किसी संबंधित वित्तीय वर्ष की 12 माह की अवधि से आरम्भ अथवा समाप्त होने वाली अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा इससे अधिक हो, तब आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, शल्य-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद-15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 तथा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा यदि निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाए :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी 12 महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं है; और
- (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया हो जो दूसरे राज्य का निवासी न हो; और
- (ग) पारिश्रमिक जो ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता हो जो नियोजक का दूसरे संविदाकारी राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा विमान पर प्रयोग किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर भी केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

4. पैराग्राफ (2) में उल्लिखित "नियोक्ता" पद में वह व्यक्ति शामिल है जिसे किए गए कार्य पर अधिकार हो और जो कार्य के निष्पादन से संबंधित जिम्मेदारी और ज़ोखिम उठा सकता हो।

अनुच्छेद-16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हों, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद-17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को किसी संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यकलापों से प्राप्त आय पर पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य का दौरा दूसरे संविदाकारी राज्य, उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा इसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हो ऐसे मामले में, आय केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी एक निवासी हो।

अनुच्छेद-18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद-19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थायी प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के किसी व्यक्ति को अदा किए गए पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।
- (ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हों और उक्त व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो, जो :
 - (i) उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक हो; अथवा
 - (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं बना हो।
2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उसमें से उस संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा;
- (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यक्ति उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

- (क) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां; और
- (ख) उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त उतनी रकम का प्राप्त प्रतिफल जो उस रकम से अधिक न हो, जिस पर किसी वित्तीय वर्ष में उस अन्य संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत कर से छूट प्राप्त होती है, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे तौर पर संबंधित हो या उसके भरण-पोषण के लिए किया जाता हो।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा माधारणतया अपेक्षित हो परन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद-21**प्रोफेसर, अध्यापक और शोध अध्येता**

1. कोई प्रोफेसर अथवा अध्यापक जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरी ऐसी संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी है अथवा था, उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य करने के लिए उसको प्राप्त किमी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, “अनुमोदित संस्था” पद से वह संस्था अभिप्रेत है जिसे संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद -22**अन्य आय**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्रोतों जैसे लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दूसरी दौड़ों, ताश और किसी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ अथवा किसी भी स्वरूप की शर्तों के संबंध में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद-23**पूंजी**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा धारित एवं दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर जो किसी स्थायी संस्थापन की व्यावसायिक सम्पत्ति का अंग है और जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे राज्य में धारित है अथवा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के कार्य-निष्पादन के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूंजी पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

3. अंतरराष्ट्रीय यातायात में प्रचालित किए गए जहाजों तथा विमानों या ऐसे जहाजों अथवा विमानों के प्रचालन से संबंधित चल सम्पत्ति द्वारा निरूपित की गई पूंजी केवल उक्त संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका कि ऐसे जलयानों, वायुयानों अथवा सम्पत्ति का प्रचालन करने वाला उद्यम निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के सभी अन्य तत्वों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-24**दोहरे कराधान का अपाकरण**

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित राज्यों में आय और पूंजी के कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे मित्राय उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके विपरीत प्रावधान किए जाएं।

2. भारत के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय अथवा रखी गई पूंजी प्राप्त करता हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार श्वेत गणराज्य में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की उक्त आय अथवा पूंजी पर उस आयकर की रकम के बराबर कर

से कटौती प्रदान करेगा जो चेक गणराज्य में अदा किया गया है चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अदा किया गया हो। तथापि ऐसी रकम कटौती दिए जाने से पहले संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय अथवा पूंजी को हो जिस पर चेक गणराज्य में कर लगाया जा सकता है।

3. चेक गणराज्य के मामले में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्न प्रकार से किया जाएगा :

जहां चेक गणराज्य का कोई निवासी ऐसी आय अथवा रखी गई पूंजी प्राप्त करता हो जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है वहां चेक गणराज्य उस निवासी की उक्त आय अथवा पूंजी पर उस आयकर की रकम के बराबर कर से कटौती प्रदान करेगा जो भारत में अदा किया गया है। तथापि, ऐसी रकम कटौती दिए जाने से पहले संगणित आयकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय अथवा पूंजी को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

4. किसी संविदाकारी राज्य में देय करों में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित वह कर भी शामिल माना जाएगा जो उक्त संविदाकारी राज्य के कानूनों को अंतर्गत दिए गए कर प्रोत्साहनों के न दिए जाने पर देय होता और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है।

5. जहां पर इस अभिसमय के किसी भी उपबंध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय अथवा रखी गई पूंजी पर उक्त राज्य में कर से छूट प्राप्त है, वहां पर भी ऐसे राज्य द्वारा ऐसे निवासी को शेष आय अथवा पूंजी पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी की धनराशि को ध्यान में रखेगा

अनुच्छेद-25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का अर्थ ऐसे किसी स्थायी संस्थापन, जो प्रथमोल्लिखित राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी का है, के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना नहीं लगाया जाएगा जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की इसी प्रकार की किसी कम्पनी के लाभों पर लगाये गये कर की दर से अधिक हो और न ही इसका अर्थ इस अभिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंध से विपरीत होना लगाया जाएगा।

3. संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या उससे तत्संबंधित कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक बोझिल है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

4. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया है। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कराधेय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनकी संविदा प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी के साथ की गई हो।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक प्रकार और विवरण के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद-26

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला पस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है और यदि उसका

मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाई की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि यह किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार कर सकते हैं जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जब समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त हो तो ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें उक्त संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद-27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों, खासकर ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपबन्धन की रोकथाम करने के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उक्त राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबंधित हों जिन पर यह अभिसमय लागू होता हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे। वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सफाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सफाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार संबंधी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना अथवा दस्तावेज प्रकट होते हों, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद - 28

वसूली सहायता

1. उन करों की वसूली में संविदाकारी राज्य एक दूसरे को सहायता देने का वचन देते हैं जो इस अभिसमय में "राजस्व दावे" के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसे करों से संबंधित व्याज, लागत तथा सिविल शास्तियों से संबंधित हैं।

2. किसी राजस्व दावे की वसूली में किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुरोध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस बात का प्रमाणन शामिल होगा कि उस राज्य के कानून के अधीन दावा किया गया राजस्व अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ राजस्व दावा तभी अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया जाता है जब किमी संविदाकारी राज्य को उसके आंतरिक कानून के अंतर्गत राजस्व दावे की वसूली करने का अधिकार हो और कर-दाता को वसूली रोकने का और कोई अधिकार प्राप्त न हो।

3. किसी करदाता से देय करों की वसूली के लिए सहायता का अनुरोध तभी किया जाएगा यदि अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता के पास करों की वसूली हेतु पर्याप्त सम्पत्तियां उपलब्ध न हों।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूल की गई राशि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दी जाएगी। तथापि प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य को उन खर्चों की प्रतिपूर्ति का हक होगा, यदि कोई हो, जो ऐसी

सहायता प्रदान करने के दौरान किए गए हैं और यह प्रतिपूर्ति उस सीमा तक की जाएगी जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच में पारस्परिक सहमति हो गई हो।

5. इस अनुच्छेद की किसी भी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य पर यह बाध्यता लागू की जाए कि वह उन प्रशासनिक उपायों से भिन्न तरह के उपाय करे जो उसके स्वयं के करों की वसूली में किए जाते हैं अथवा वह ऐसे प्रशासनिक उपाय करे जो कि उसकी सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हों।

6. इस अभिसमय के प्रवृत्त होने से संबंधित अनुच्छेद 30 के उपबंधों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद की प्रयोज्यता संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच परस्पर सहमति की तारीख से शुरू होगी।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशनों तथा कौंसुली पदों के सदस्य

इस अभिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशनों या कौंसुली पदों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस अभिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा किए जाने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह अभिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

3. इस अभिसमय के उपबंध निम्न प्रकार से प्रभावी होंगे :

(क) भारत में जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय अथवा धारित पूंजी के संबंध में;

(ख) चेक गणराज्य में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई आय की राशि पर स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में आय अथवा पूंजी के लिए आय और पूंजी पर अन्य करों के संबंध में।

4. इस अभिसमय के प्रभावी होने पर भारत और चेक गणराज्य के बीच इस संबंध में 27 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत सरकार और चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार की प्रयोज्यता प्रभावी होना समाप्त हो जाएगी।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह अभिसमय अनिश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर अभिसमय को समाप्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में अभिसमय निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) भारत में जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त होने वाली आय के संबंध में और जिस कैलेण्डर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अगले वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर पारित पूंजी के संबंध में;

(ख) चेक गणराज्य में :

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई आय की राशि पर स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में ;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में आय अथवा पूंजी के लिए आय और पूंजी पर अन्य करों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष एक हजार नौ सौ अठ्ठानवे के अक्टूबर माह के पहले दिन, हिन्दी, अंग्रेजी और चेक भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(गिरीश धुमे)

चेक गणराज्य की
सरकार की ओर से
(इवो स्योबोदा)

[अधिसूचना सं. 11160/फा. सं. 503/6/93-वि. क. प्र.]

विजय माधुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 1999

G. S. R. 811 (E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Czech Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on Capital has come into force on the 27th day of September, 1999, on the Notification by both the Contracting States of each other, under article 30 of the said Convention, of the completion of the procedures required under their respective laws for bringing into force of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 44A of the Wealth-tax Act, 1967 (27 of 1967), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**CONVENTION****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL.**

The Government of the Republic of India and the Government of the Czech Republic

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital and with a view to promoting economic cooperation between the two countries,

have agreed as follows :

Article 1**PERSONAL SCOPE**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2**TAXES COVERED**

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income, or capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular :
 - (a) In India :
 - (i) the income tax, including any surcharge thereon;
 - (ii) the wealth tax,
(hereinafter referred to as "Indian tax");
 - (b) In the Czech Republic :
 - (i) the tax on income of individuals;
 - (ii) the tax on income of legal persons;

- (iii) the tax on immovable property,
(hereinafter referred to as “Czech tax”);

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- (b) the term “the Czech Republic” means the territory of the Czech Republic over which, under Czech legislation and in accordance with international law, the sovereign rights of the Czech Republic are exercised;
- (c) the term “person” includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (g) the term “competent authority” means :
 - (i) in India: the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
 - (ii) in the Czech Republic, the Ministry of Finance or his authorised representative;
- (h) the term “national” means :
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (i) the term “fiscal year” means :
 - (i) in the case of India, “previous year” as defined under section 3 of the Income-tax Act, 1961;
 - (ii) in the case of the Czech Republic, calendar year;
- (j) the term “tax” means Indian tax or Czech tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;
- (k) the term “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Republic of India or the Czech Republic as the context requires.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4**RESIDENT**

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5**PERMANENT ESTABLISHMENT**

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a sales outlet;
- (h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
- (i) a farm plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.

3. A building site or construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment only if such site, project or activities last more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person :

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
- (b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, aircraft and motor vehicles shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7**BUSINESS PROFITS**

1. The profit of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reasons of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8**SHIPPING AND AIR TRANSPORT**

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircrafts in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of container (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.

3. For the purposes of this Article, interest on funds directly connected with the operations of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraphs 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9**ASSOCIATED ENTERPRISES**

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10**DIVIDENDS**

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11**INTEREST**

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State provided it is derived and beneficially owned by, or derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :
 - (a) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (b) (i) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export-Import Bank of India, the National Housing Bank, the Small Industries Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); and
 - (ii) in the case of the Czech Republic, the Czech National Bank (CNB), the Czech Export Bank (CEB), the Export Guarantee and Insurance Company (EGAP), and the Konsolidation Bank (KoB); or
 - (c) any other institution as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States.
4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent

establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in the Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) the term "fees for technical services" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in articles 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a contracting state when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or nor, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13**CAPITAL GAINS**

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircrafts operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State :
 - (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - (b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

Article 15**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if all the following conditions are met :
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

4. The term "employer" mentioned in paragraph 2 (b) covers the person having right on the work produced and bearing the responsibility and risk connected with the performance of the work.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by an entertainer or a sportsperson if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or of political subdivisions or local authorities thereof. In such case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20**STUDENTS AND APPRENTICES**

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training shall, besides grants, loans and scholarships, be exempt from tax in that other state on:

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training: and
- (b) remuneration from employment in that other State, for an amount not exceeding the amount which is exempt from tax under the laws of that other Contracting State for any fiscal year, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than seven consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 21**PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS**

1. A professor or teacher who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1 the term "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned State.

Article 22**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

Article 23**CAPITAL**

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may also be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft, operated in international traffic or by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise operating such ships, aircraft or property is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income and of capital in the respective Contracting State except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. In the case of India double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the Czech Republic, India shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in the Czech Republic whether directly or by deduction at source. Such amount shall not however exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or capital which may be taxed in the Czech Republic.

3. In the case of the Czech Republic double taxation shall be eliminated as follows :

Where a resident of the Czech Republic derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, the Czech Republic shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or capital which may be taxed in India.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraph 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Where, in accordance with any provision of this Convention, income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27**EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, or documents the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28**COLLECTION ASSISTANCE**

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interests, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim".

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.

3. A request for assistance in collection of taxes due from a tax payer shall be made only if adequate assets of that tax payer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

4. Amount collected by the competent authority of a contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.

5. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

6. Notwithstanding the provisions of Article 30 relating to entry into force of this convention, the application of this Article shall commence on a date to be mutually agreed upon by the competent authorities of the Contracting State.

Article 29

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedure required by the respective laws for the entry into force of this convention.

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Convention shall have effect :

- (a) in India, in respect of income derived or capital held in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force ; and
- (b) in the Czech Republic :
 - (i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after first January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force ;
 - (ii) in respect of other taxes on income and taxes on capital, to income or capital in any taxable year beginning on or after first January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

4. On the entry into effect of this Convention, the application of the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at New Delhi on 27th January 1986 shall, in relation between the Czech Republic and India, cease to have effect.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income derived in any previous year on or after the first April next following the calendar year in which the notice is given and in respect of capital held at the expiry of any previous year beginning on or after first April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in the Czech Republic,
 - (i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after first January in the calendar year next following that in which the notice is given;

- (ii) in respect of other taxes on income and taxes on capital, to income or capital in any taxable year beginning on or after first January in the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at PRAGUE this 1st day of Oct. 1998 in Hindi, English and Czech languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence between the texts the English text shall be the operative one.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

(GIRISH DHULE)

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE CZECH REPUBLIC**

(IVO SUOBODA)

[Notification No. 11160/F.No. 503/6/93-FTD]
VIJAY MATHUR, Jt. Secy.